उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक क्षेत्र में मिलेंगी डेढ़ लाख नौकरियां : डावरा

बोले विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर सकते हैं राज्य

संवाद न्यूज एजेंसी

वाराणसी। वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से राज्य के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षमता में विकास हुआ है।

इसमें आठ अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे, भारत का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग (एनडब्लू-1) और 20 जिलों से होकर गुजरने वाला 1100 किमी का डीएफसी ट्रैक शामिल है। इससे लाजिस्टिक क्षेत्र में करीब एक लाख 48 हजार रोजगार सृजन होगा। यूपी ने राज्य के प्रत्येक औद्योगिक पार्क और अंचल में रसद क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया है। इससे डेढ़ लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। यह कहना है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में मौजूद छह राज्यों के प्रतिनिधि। अमर उजाला

में विशेष सचिव सुमिता डावरा का। वह बुधवार को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) विषयक दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य रियायती शर्तों पर आसान वित्तीय मदद के लिए लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर सकते हैं। राज्य उत्पादित माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए समितियों की स्थापना कर योजनाओं का विकास करें। उन्होंने पीएम गति शक्ति और कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों को अंतर-विभागीय व व्यापारिक बैठकें करने की अपील की है।

साथ ही कहा कि मानव संसाधन विकास, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर मिलकर काम करने की जरूरत है। इसे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जगह दी जा सकती है। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सकती है।

विशेष सचिव ने लॉजिस्टिक्स सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने की सलाह दी और कहा कि इसमें क्षेत्रीय व्यापार संघों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। समापन के दौरान प्रतिभागियों को बुलंदशहर के ओडीओपी के उत्पाद भेंट किए गए। इस मौके पर अभिषेक श्रीवास्तव, एलके रज्जाक, तपन कुमार मिश्र, मिहिर शाह ने प्रस्तुति दी।